भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1286
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

1286. श्री जी. सेल्वम :
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) ने देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया है;
(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मछली उत्पादन का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसी योजना तमिलनाडु राज्य में कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुल कितनी निधियाँ प्रदान की गई हैं;
और
(घ) ऐसी अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में मत्स्यपालन योजनाओं से कितने किसानों/परिवारों को लाभ हुआ है;
(ङ) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20050 करोड़ रूपये के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है । पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत चार वर्षों के दौरान, देश में मत्स्य उत्पादन 2020-21 में 147.25 लाख टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 182.70 लाख टन (अनुमानित) हो गया है । इसी तरह, तमिलनाडु राज्य में मत्स्य उत्पादन भी 2020-21 के दौरान 7.23 लाख टन से बढ़कर 2023-24 के दौरान 8.84 लाख टन हो गया है ।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में तथा तमिलनाडु राज्य में मत्स्य उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ष	देश में मत्स्य उत्पादन (लाख टन में)	तमिलनाडु राज्य में मत्स्य उत्पादन (लाख टन में)
1	2020-21	147.25	7.23
2	2021-22	162.50	8.07
3	2022-23	175.45	8.29
4	2023-24	182.70	8.84

(ग) से (ड़) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन के विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) के दौरान तमिलनाडु सरकार के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 932.39 करोड़ रु/- की लागत से मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र का अंश 375.44 करोड़ रु/- है । तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट किया है कि राज्य में पीएमएमएसवाई के कारण कुल 175139 किसान/परिवार लाभान्वित हुए हैं । पीएमएमएसवाई में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हार्वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचा स्थापित करने और मछुआरों के कल्याण में कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने की परिकल्पना की गई है । इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि गहनता(इंटेनसिफीकेशन), क्षेत्र विस्तार, मात्स्यिकी गतिविधियों का विविधीकरण, प्रौद्योगिकियों का समावेश, मत्स्य स्टॉक वृद्धि गतिविधियाँ (रिवर और सी रेंचिंग), डीप सी फिशिंग को बढ़ावा देना, ओपन सी केज सहित मेरीकल्चर को प्रोत्साहन, सी वीड और बाईवाल कल्चर, गुणवत्ता वाले बीज और चारे की आपूर्ति, सतत मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देना, आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास, जलाशयों में केज कल्चर सहित एकीकृत जलाशय विकास, लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों में फिश कल्चर को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा, फिशेरीस इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (एफआईडीएफ) के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग ने तमिलनाडु राज्य में 1577.08 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए 66 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

*****